



HAL
open science

Share on Back Benches: Caste Composition of Bihar's Media

Pramod Ranjan

► **To cite this version:**

Pramod Ranjan. Share on Back Benches: Caste Composition of Bihar's Media. Forward press, 2011, 3 (6), pp.21-26. 10.31235/osf.io/527bt . hal-03936825

HAL Id: hal-03936825

<https://hal.science/hal-03936825>

Submitted on 12 Jan 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial 4.0 International License

Share on Back Benches

Caste Composition of Bihar's Media

पिछली सीटों पर हिस्सेदारी बिहार के मीडिया की जातीय संरचना

PRAMOD RANJAN

About five years ago, the blatant partisanship of the media in favour of the anti-reservation campaign prompted Delhi's Media Studies Group to carry out a survey on the social backgrounds of journalists occupying the highest posts in both the Hindi- and English-language media in Delhi. This survey of 37 Delhi-based media institutions collected information about the social background of at least 10 top journalists of each institution. In the national media, the authoritative positions are overwhelmingly (71 per cent) occupied by high-caste Hindu men. Four per cent were found to be from backward classes and high-caste Hindu women occupied 7 per cent of such positions. The number of Muslims, Dalits and tribals was however zero.

When media in the national capital presents such a grim picture one cannot hope for much from the "backward" states. In 2009 we adopted the same techniques for a survey of Bihar's media institutions, which left us with some disturbing results.

Those 37 media institutions which were included in the survey of national media institutions were headquartered mostly in Delhi and so they had a sufficient number of influential high posts. So the selection of top 10 positions was possible and feasible. This was not the case in the media institutions of Patna. In media institutions of Patna, we identified the following five posts as authoritative: (1) Editor, (2) News Editor, (3) Bureau Chief, (4) Main/Special Correspondent and (5) Province Desk In-Charge.

Several media institutions of Patna lack even the above-listed five posts. Most newspapers, news agencies and electronic channels employ very few journalists. In fact, many bureau offices of national media institutions situated in Patna only have the post of a

प्रमोद रंजन

लगभग पाँच साल पहले, आरक्षण विरोधी अभियान के प्रति मीडिया के प्रति घोर पक्षपातपूर्ण रवैये को देखते हुए दिल्ली के मीडिया स्टडीज़ ग्रुप को हिंदी एवं अंग्रेज़ी भाषा के राष्ट्रीय मीडिया के प्रमुख पदों पर कार्यरत लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि का सर्वेक्षण करने के लिए प्रेरित किया। दिल्ली स्थित 37 मीडिया संस्थानों में किए गए उस सर्वेक्षण में हर एक संस्थान के कम से कम 10 सर्वोच्च पदों पर काबिज़ पत्रकारों की सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी हासिल की गई थी। राष्ट्रीय मीडिया में 'फ़ैसला लेने वाले' पदों पर उच्च जाति हिंदू पुरुषों का हिस्सा 71 फ़ीसदी था। पिछड़े 4 फ़ीसदी थे। उच्च जाति हिंदू महिलाओं की मौजूदगी 17 प्रतिशत थी। दलित और आदिवासियों की संख्या शून्य थी।

जब राष्ट्रीय राजधानी में मीडिया की तस्वीरें इतनी निराशाजनक हैं तो "पिछड़े" राज्यों से क्या उम्मीद की जा सकती है। साल 2009 में हमने बिहार के मीडिया संस्थानों के सर्वेक्षण के लिए शुरू में हमने भी यही तकनीक अपनायी, जिसके किंकर्तव्यविमूढ़ कर देने वाले परिणाम सामने आए।

राष्ट्रीय मीडिया के सर्वेक्षण में जिन 37 संस्थानों को शामिल किया गया था, उनमें से अधिकांश का मुख्यालय दिल्ली में ही होने के कारण "बड़े" पदों की संख्या पर्याप्त थी। इसलिए सर्वोच्च 10 पदों को चुनना संभव था। पटना के मीडिया संस्थानों में हमने पाँच पदों - (1) संपादक, (2) समाचार संपादक, (3) ब्यूरो चीफ़, (4) मुख्य/विशेष संवाददाता और (5) प्रोविंस डेस्क इंचार्ज - को 'फ़ैसला लेने वाले' के रूप में चिन्हित किया।

पटना के अनेक मीडिया संस्थानों में उपरोक्त सभी पाँच पद भी नहीं हैं। कई अखबारों, समाचार एजेंसियों और इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में कार्यरत पत्रकारों की संख्या बहुत कम है तथा यहां कार्यरत कई राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों के ब्यूरो कार्यालयों में तो अकेले (ब्यूरो) "चीफ़" का ही पद है। ऐसी स्थिति में इन पदों के समकक्ष कार्य कर रहे लोगों को भी 'फ़ैसला लेने वाला' माना गया। ऐसे पत्रकारों की संख्या किसी संस्थान में पाँच, कहीं तीन, कहीं दो हैं तो

Bureau Chief. In such situations, people working in posts equivalent to the above-listed posts were also considered as authoritative. The numbers of such journalists in several offices are as low as five or three or even two; in many offices the Bureau Chief alone has executive authority. Hence, 78 journalists working in high posts at the state level, from 42 different media institutions, were surveyed about their social background. These included Hindi and English (Urdu not included) newspapers, electronic media, news agencies and magazines.

This survey included only those journalists who are connected to “news”. Twenty journalists each, in descending order, were chosen from those newspapers which employed a large number of journalists (Hindustan, Dainik Jagran, Prabhat Khabar and Rashtriya Sahara), while almost all journalists from other small newspapers were covered (the number ranging from 4 to 13 per paper). The same formula was applied to electronic channels as well. The heads of Patna division of Delhi and other metro cities-based national media institutions were also included in this survey. Such daily newspapers, magazines, news channels and news agencies often have only one or two journalist posted in Patna. They all have been included in this survey.

THE BEGINNING

The idea of a survey emerged after the devastating flooding in River Kosi in August 2008. Thousands of people lost their lives in this

कहीं अकेले ‘ब्यूरो चीफ’ ही ‘फ़ैसला’ लेते हैं। इसके तहत 42 मीडिया संस्थानों के राज्यस्तरीय सर्वोच्च पदों पर कार्यरत 78 पत्रकारों की पृष्ठभूमि जाँची गई इनमें हिंदी-अंग्रेज़ी प्रिंट (उर्दू नहीं), इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान, समाचार एजेंसियां व पत्रिकाएं शामिल थीं।

इस सर्वेक्षण में उन्हीं पत्रकारों को शामिल किया गया जो ‘खबरो’ से जुड़े हैं। फ़ीचर आदि प्रभागों को इसमें शामिल नहीं किया गया। अधिक पत्रकारों वाले अखबारों, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर और राष्ट्रीय सहारा से अक्टोबी (ऊपर से नीचे) क्रम में 20-20 पत्रकारों को लिया गया। जबकि अन्य छोटे अखबारों के लगभग सभी पत्रकारों (यह संख्या प्रति अखबार 4 से लेकर 13 तक रही) को शामिल किया गया। यह फ़ॉर्मूला इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर भी लागू किया गया। दिल्ली समेत अन्य महानगरों से संचालित होने वाले राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों के पटना प्रमुखों को भी इसमें रखा गया है। ऐसे दैनिक समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, न्यूज चैनलों और समाचार एजेंसियों के प्रायः दो या एक ही पत्रकार पटना में पदस्थापित हैं। इन सभी को इसमें शामिल किया गया है।

शुरूआत के शुरू में

सर्वे का विचार वस्तुतः अगस्त 2008 में कोसी नदी में आई प्रलयकारी बाढ़ के बाद आया था। बाढ़ में हजारों लोग मारे गए थे। जिस इलाके में बाढ़ आई थी, वह यादव और दलित बहुल था। जबकि राज्य में एक ऐसी सरकार थी जो यादव राज खत्म कर चुकने की दुदुभी बजाती फिर रही थी। इस नई सरकार के एक घटक (जद-यू) का मुख्य वोट बैंक भूमिहार, कुरमी-कोईरी और अत्यंत पिछड़ी जातियाँ हैं। जबकि दूसरे घटक (भाजपा) का वोट बैंक

ENGLISH PRINT IS VISIBLY DOMINATED BY BRAHMINS (36 PER CENT) AND KAYASTH (21 PER CENT)

अंग्रेज़ी प्रिंट पर ब्राह्मणों (36 प्रतिशत) तथा कायस्थों (21 प्रतिशत) का आधिपत्य दिखता है

flood. The area in which the floods occurred was dominated by Yadavs and Dalits. The state government, led by the Janata Dal (United) [JD (U)], boasted about abolishing Yadav Raj completely, and the main vote bank of this new government consisted mainly of Bhumihars, Kurmi-Koeri and other extremely backward castes; the BJP, its main ally, had its vote bank full of Vaishya and other affluent castes. Now this government of feudal values was extremely cruel and careless in delivering relief to the victims of the disastrous flood. Both the ruling and opposition parties indulged in extremely contemptible class-caste politics. In spite of all this, Bihar’s media was not only silent on such cheap politics but there seemed to be a competition within its ranks for portraying the flood’s ravages as minimal and the flood relief work of the state government as exaggerated as possible. This despicable behaviour of Bihar’s journalists initially challenged us to carry out a survey on the geographical background of journalists working in Patna. We asked a couple of questions: How many Patna journalists belong to the flood-affected districts? Is it possible that since not many come from those districts, they are less sensitive to the misery of the people there? Thus we began.

We thought it would be quite easy; two or three colleagues together will be easily able to deal with it. But we were dealing with

वैश्यों तथा अन्य स्वर्ण जातियों में है। सामंती संस्कार वाली यह सरकार बाढ़ की तबाही के लगभग दो महीने तक पीड़ितों को राहत पहुँचाने में बेहद क्रूर कोताही बरतती रही। इस मामले पर पक्ष और विपक्ष दोनों की राजनीति अत्यंत निचले किस्म की जाति-आधारित थी, इसके बावजूद बिहार की पत्रकारिता न सिर्फ़ इस घटिया राजनीति पर मौन थी बल्कि उसमें बाढ़ की विभीषिका को कम से कम कर दिखाने और राज्य सरकार के राहत कार्यों को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाने की होड़ लगी थी। पत्रकारिता के इस जघन्य दुष्कर्म ने आरंभ में हमें पटना में कार्यरत पत्रकारों की भौगोलिक पृष्ठभूमि के सर्वेक्षण के लिए प्रेरित किया। हमारे सामने एक खयाल था कि क्या राजधानी पटना में कार्यरत पत्रकारों में बहुत कम संख्या कोसी की बाढ़ग्रस्त जिलों के वासियों की है? क्या इसलिए वे अपनी पेशागत ज़रूरतों के विपरीत बाढ़ पीड़ितों के प्रति इतने कम संवेदनशील हैं? काम शुरू हुआ। हम इसे बेहद आसान समझ रहे थे। हमारी सोच थी कि हम दो-तीन सहकर्मी मिलकर आसानी से निपटा लेंगे। लेकिन जिस भूखंड में आदमी की मुख्य पहचान जाति हो, वहां क्या शिक्षा, और क्या भूगोल, सब द्वितीय किस्म के परिचय है। हम किन्हीं दो पत्रकारों से किसी तीसरे पत्रकार का गृह जिला पूछते तो उनमें कोई सहमति नहीं होती। लेकिन दोनों ही बिना पूछे ही उसकी जाति खुद ही बता डालते और उसमें दोनों एकमत होते हैं।

इस सर्वेक्षण में बकायदा सभी मीडिया संस्थानों के ‘राज्य स्तर पर फ़ैसला लेने वाले’ पत्रकारों की सूची तैयार की गई उनके नाम, गृह जिला, शिक्षा, धर्म और जाति के कॉलमों को विभिन्न स्रोतों से जानकारी लेकर

Consolidated statistics: Community Composition of Hindi, English, Urdu Print and Electronic Media

(On normal positions apart from decision-making positions)

समेकित आँकड़े: हिंदी, अँग्रेजी, उर्दू प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सामुदायिक संरचना (सामान्य पदों पर, फैसला लेने वाले पदों के अलावा)

CASTES / COMMUNITIES जाति/समुदाय	IN MEDIA मीडिया में मौजूदगी	IN BIHAR बिहार में जनसंख्या
1. UPPER-CASTE HINDU 1. उच्चजातीय हिंदू	73%	13%
A. Brahmin क. ब्राह्मण	30%	4.7%
B. Bhumihar ख. भूमिहार	10%	2.9%
C. Rajput ग. राजपूत	17%	4.2%
D. Kayastha घ. कायस्थ	16%	1.2%
2. BACKWARD AND MOST BACKWARD CASTES 2. पिछड़ी एवं अत्यंत पिछड़ी जातियाँ	10%	51.5%
3. DALIT 3. दलित	1%	14.1%
4. UPPER-CASTE MUSLIMS 4. उच्चजातीय मुस्लिम	12%	3.37%
A. Syed क. सेयद	8%	
B. Shaikh ख. शेख	2%	
C. Pathan ग. पठान	1%	
D. Mallik घ. मलिक	1%	
5. PASMANDA (BACKWARD) MUSLIMS 5. पसमांदा मुस्लिम	4%	10.13%
6. WOMEN 6. महिलाएँ	4%	
A. Upper-caste Hindu क. उच्चजातीय हिंदू	3%	
B. Backward ख. पिछड़ी	1%	
C. Dalit ग. दलित	0%	
D. Muslims (Upper Castes/Pasmanda (Backward)) घ. मुस्लिम (उच्चजातीय/पसमांदा)	0%	

IF WE ASKED TWO journalists about the native district of a third journalist, they could not seem to agree, but both would answer the unasked question about the other journalist's caste, and they would both agree

हम किन्हीं दो पत्रकारों से तीसरे पत्रकार का गृह जिला पूछते हैं तो उनमें कोई सहमति नहीं होती। लेकिन दोनों के बिना पूछें ही उसकी जाति खुद बता डालते और उसमें दोनों एकमत होते हैं।

NOTE:
Population of Upper-caste Hindu and Backwards based on 1931 census

नोट:
उच्चजातीय हिंदुओं और पिछड़ों की जनसंख्या 1931 की जनगणना पर आधारित

that part of the world where the primary identity of a human being is his caste; where even education and geographical backgrounds are all secondary introductions. If we asked two journalists about the native district of a third journalist, they could not seem to agree, but both would answer the unasked question about the other journalist's caste, and they would both agree.

For the survey, a list was systematically prepared of the authoritative people at state-level media institutions. The columns regarding their name, home town, education, religion and caste were being filled with the help of information gathered from various sources. In this, journalists of 42 Hindi and English media were included, from which we were able to collect information about religion, caste, sex, etc., of journalists.

SEARCH FOR INVISIBLE BACKWARD JOURNALISTS

In the first-pass survey we could not find any journalists from the deprived sections of society in authoritative positions. Suspecting that even if they have not become classroom monitors, they can be found somewhere on the back benches, we decided in June 2009 to enlarge the scope of the survey. This time, in addition to the 42 institutions of Hindi and English media, 5 Urdu newspapers published from Patna were also included in the survey. Covering 230 journalists of 47 media institutions in the survey, we found that 73 per cent posts are held by upper-caste Hindus (Brahmin, Bhumi-har, Rajput, Kayastha). OBC Hindus have only 10 per cent; Muslim Ashrafs 12 per cent and 4 per cent is covered by Pasmanda (Backward) Muslims. The presence of women is about 4 per cent. We found only 3 Dalit journalists in media institutions in Patna (Table P. 23).

HINDI PRINT: 87/13

Eighty-seven per cent of journalists working in Hindi newspapers and magazines in Patna belong to upper-caste Hindu families. Of these 34 per cent are Brahmin, 23 per cent are Rajput, 14 per cent are Bhumi-har and 16 per cent are Kayastha. Journalists from Hindu backward and most backward castes, Ashraf Muslims and Dalit community together constitute just 13 per cent. The presence of Bihar's biggest caste Yadav is about 3 per cent. Other journalists coming from OBCs belongs to Vysya, Kushwaha, Kanu, Kewat, Kumhar and Chaurasia castes. Their presence is about 1 per cent each. In addition, any representation of other dozens of backward-most backward castes is seen in neither Hindi nor English media (print as well as electronic). The participation of high-caste Hindu women in Hindi print media is 1 per cent.

ENGLISH PRINT: WOMEN'S PRESENCE

The position of English newspaper resembles the one-eyed king. Once again, high-caste Hindus occupy 75 per cent of the positions. It has 7 per cent women's participation. The presence of 4 per cent backward class women also grabs one's attention. Hindu OBCs' presence in English print (19 per cent) is double that in Hindi print (9 per cent). Ashraf Muslims make up to 4 per cent. There are no

भरने का काम शुरू किया गया। इसमें हिंदी और अँग्रेजी के 42 संस्थानों के पत्रकारों के धर्म, जाति, लिंग की जानकारी हम जमा कर पाए।

उपस्थिति की तलाश

प्रारंभिक सर्वेक्षण में हमने पाया कि 'फ़ैसला लेने वाले पदों' पर वंचित तबके के लोग नहीं हैं। हमें शक था कि भले ही वे कक्षा में दलपति न बन सके हों, लेकिन उनको पिछले बँचों पर तो देखा ही जा सकता है, जून 2009 में हमने इस सर्वेक्षण का दायरा बढ़ाने का फ़ैसला किया। इस बार हिंदी और अँग्रेजी के 42 संस्थानों के अलावा पटना से प्रकाशित उर्दू के पाँच अखबारों को भी इसमें शामिल किया गया। कुल 47 मीडिया के संस्थानों के 230 पत्रकारों को सर्वेक्षण में समेटते हुए हमने पाया कि 73 फ़ीसदी पदों पर ऊँची जाति के हिंदुओं (ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ) का कब्ज़ा है। अन्य पिछड़ा वर्ग के हिंदू 10 फ़ीसदी, अशराफ़ मुसलमान 12 फ़ीसदी तथा पसमांदा मुसलमान 4 फ़ीसदी हैं। महिलाओं की उपस्थिति लगभग 4 फ़ीसदी रही। पटना के मीडिया संस्थानों में महज तीन पत्रकार मिले (तालिका पेज 23)।

हिंदी प्रिंट : 87/13

बिहार की राजधानी में काम कर रहे हिंदी समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के पत्रकारों में 87 फ़ीसदी पत्रकार सवर्ण हिंदू परिवारों से हैं। इनमें 34 फ़ीसदी ब्राह्मण, 23 फ़ीसदी राजपूत, 14 फ़ीसदी भूमिहार, तथा 16 फ़ीसदी कायस्थ हैं। हिंदू पिछड़ी-अति पिछड़ी जाति, अशराफ़ मुसलमान और दलित समाज से आने वाले पत्रकार महज 13 फ़ीसदी हैं। इनमें बिहार की सबसे बड़ी जाति यादव की उपस्थिति सर्वाधिक, लगभग 3 फ़ीसदी है। ओबीसी से आने वाले अन्य पत्रकार वैश्य, कुशवाहा, कानू, केवट, कहार और चौरसिया जातियों के हैं। इनकी मौजूदगी प्रायः 1-1 फ़ीसदी है। इसके अतिरिक्त अन्य दर्जनों पिछड़ी-अति पिछड़ी जातियों की कोई नुमाइंदगी न हिंदी-अँग्रेजी प्रिंट में दिखती है, न ही इलेक्ट्रॉनिक में। हिंदी प्रिंट में महिला (उच्च जाति हिंदू) की भागीदारी एक फ़ीसदी है।

अँग्रेजी प्रिंट: महिलाओं की मौजूदगी

अँग्रेजी अखबारों की स्थिति काना राजा की सी है। यहाँ उच्च जाति हिंदू 75 प्रतिशत पदों पर काबिज हैं। इसमें महिलाओं की भागीदारी 7 फ़ीसदी है। इसमें से पिछड़ी जाति की 4 फ़ीसदी महिलाओं की मौजूदगी भी ध्यान खींचती है। हिंदू ओबीसी की उपस्थिति हिंदी प्रिंट (9 फ़ीसदी) की तुलना में अँग्रेजी प्रिंट में दुगुनी से ज्यादा (19 फ़ीसदी) है। अशराफ़ मुसलमान 4 प्रतिशत हैं। दलितों की उपस्थिति शून्य है।

हिंदी और अँग्रेजी प्रिंट में एक रोचक अंतर भूमिहार और राजपूतों की संख्या का है। हिंदी प्रिंट की तुलना में यहाँ इन दो जातियों की संख्या आधी से भी कम (राजपूत 11 फ़ीसदी और भूमिहार 6 फ़ीसदी) हो गई है। अँग्रेजी प्रिंट पर ब्राह्मणों (36 प्रतिशत) तथा कायस्थों (21 प्रतिशत) का आधिपत्य दिखता है। अँग्रेजी प्रिंट में तीन हिंदू ओबीसी, एक ईसाई व एक अशराफ़ मुसलमान (पुरुष) फ़ैसला लेने वाले पद पर भी हैं। हिंदी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक में इन पदों पर निरपवाद रूप से ऊँची जाति के पुरुष काबिज हैं।

इलेक्ट्रॉनिक : 10 बनाम 90

पिछड़े नेता शहीद जगवेद प्रसाद का नारा था - "दस का शासन नब्बे पर, नहीं चलेगा/ सौ में नब्बे शोषित हैं, नब्बे भाग हमारा है।" यह 1971-72 की बात है। लेकिन आज तक अन्य पिछड़ा वर्ग का सामाजिक-राजनीतिक नेतृत्व ज्ञान की सत्ता पर काबिज होने के रास्तों को पहचानने में नाकाम रहा है। सांस्कृतिक सत्ता का तो इनके लिए कोई मोल नहीं रहा। 100 में से 90 का दावा करने वाले जगदेव का दूसरा नारा यह भी था - "भैंस पालो, अखाड़ा खोदो, राजनीति करो।" लालू प्रसाद ने तो 15 साल आइटी को समझने से

Attack on Prem Kumar Mani, MLC merits single column only

प्रेमकुमार मणि, एमएलसी, पर हमला बस एक कॉलम की खबर



To understand the character of Bihar media, it will be enough to mention a recent incident.

On the night of 5 May 2011, a deadly attack was carried out at the residence of writer and intellectual Prem Kumar Mani. The police have ruled out robbery as a motive. With the obvious intention of murdering him, a few people broke into Mani's Patna residence. Incidentally, that night Mani was not sleeping in the particular room he usually sleeps in. The killers could not find him and left empty handed.

A few days prior to this incident, the father of the JD(U) treasurer, writer Sita Ram Yadav was attacked in a similar manner and killed in Patna. The killers had broken in through a window and killed Yadav by hitting him on the head with a sledgehammer. Not just that, the killers did not immediately flee after the murder, they dragged the body of the dead writer, left it outside the house and only then did they go. A few years back, historian Papiya Ghosh was killed in Patna in similar fashion. Till today, there's no clue of the killers. There is one similarity in all three incidents - nothing was stolen from the house. This means that burglary or robbery was not the reason behind any of these three incidents.

Prem Kumar Mani has been the founder member of the ruling Janata Dal (U) and is also a member of the Bihar legislative council. In April, on the insistence of Chief Minister Nitish Kumar, he was suspended from the party for six years. He was charged with indiscipline. Mani had strongly criticized the CM for constituting the Savarna Aayog. In its May issue, FORWARD Press had published his article "Interrogating Bihar's Savarna Commission".

It is obvious that this incident concerning Mani comes as a great shock to those people who understand Mani's contribution in making the ideology of social justice in North India a success. As a writer, he has a huge country-wide following. Despite that, the Bihar print media has tried to present this incident as if nothing really happened. Most newspapers have dealt with this news in a single column, whereas from all accounts this was a big incident. For a newspaper in any state, such an incident at a legislator's house is huge news. And for the newspapers who had announced the end of crime in Bihar and the arrival of good governance, this news should definitely have been big news. If the residence of a legislator, who lives under government security, is attacked in such a way, then what will be the condition of the aam janata?

Evidently, for the last six years, Bihar media has tried to turn a deaf ear to all the voices that go against Nitish Kumar. Perhaps it is not necessary to explain separately as to how dangerous is media that is on the short leashed of selfish motives, casteist assumptions and government advertisements.

बिहार के मीडिया के चरित्र को समझने के लिए हाल की एक घटना काफी होगी।

गत 5 मई 2011 की रात लेखक व चिंतक प्रेमकुमार मणि के आवास पर जानलेवा हमला किया गया। पुलिस ने लूट के इशारे को नकार दिया है। स्पष्ट है कि मणि के पटना स्थित आवास में कुछ लोग उनकी हत्या के इशारे से खिड़की तोड़ कर घुसे थे। संयोग से मणि उस रात उस कमरे में नहीं सोए थे जिसमें योजना सोते थे। हत्यारे मणि को तलाश नहीं सके और बैरंग लौट गए।

इसके कुछ दिन पहले पटना में ठीक इसी तरह जनता दल (यू) के कोषाध्यक्ष के पिता व लेखक सीताराम यादव की हत्या की गई थी। हत्यारे ठीक इसी तरह खिड़की तोड़ कर सीताराम यादव के घर में घुसे थे और सिर पर हथौड़ा मार कर उनकी हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद हत्यारे फ़रार नहीं हुए बल्कि उन्होंने दिवंगत यादव की लाश को घसीट कर घर के बाहर किया, उसके बाद गए। कुछ साल पहले पटना में इतिहासकार पापिया घोष की हत्या भी इसी तरह की गई थी। इन तीनों घटनाओं में एक समानता यह भी है कि घर का कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ। यानी तीनों घटनाएँ चोरी या लूट के इशारे से नहीं की गई थीं।

प्रेमकुमार मणि बिहार की सत्ताधारी पार्टी जनता दल (यू) संस्थापक सदस्य रहे हैं और बिहार विधान परिषद् के सदस्य भी हैं। अप्रैल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर उन्हें पार्टी से छह वर्षों के लिए निलंबित कर दिया गया था। आरोप अनुशासनहीनता का था। मणि ने सर्वार्थ आयोग का गठन करने के लिए मुख्यमंत्री का मुखर विरोध किया है। फॉरवर्ड प्रेस ने मई अंक में उनका लेख "सर्वार्थ आयोग पर सवाल" प्रकाशित किया था।

जाहिर है मणि के साथ हुई इस घटना उन लोगों के लिए गहरा सदमा है जो उत्तर भारत में सामाजिक न्याय की विचारधारा के फलीभूत होने में मणि के योगदान को समझते हैं। बतौर कथा लेखक भी देशभर में उनके प्रशंसकों की बड़ी संख्या है। इसके बावजूद बिहार के मीडिया ने इस घटना को ऐसे पेश करने की कोशिश की मानो कुछ हुआ ही न हो। प्रायः सभी समाचारपत्रों ने इस समाचार को सिर्फ एक कॉलम में निपटार दिया। जबकि हर दृष्टिकोण से यह एक बड़ी घटना थी। किसी विधायक के घर पर हुई ऐसी घटना किसी भी राज्य के अखबार के लिए बड़ी घटना होती है। बिहार में अपराध के खत्म हो जाने और कथित सुशासन के आगमन की घोषणा करने वाले अखबारों के लिए तो निरर्थक ही यह बहुत बड़ी खबर होनी चाहिए थी। जब सरकारी सुरक्षा में रहने वाले विधायक के घर पर हमला हो रहा है तो आम जनता की वहाँ क्या हालत होगी?

वस्तुतः बिहार के मीडिया ने पिछले छह वर्षों में नीतीश कुमार के विरुद्ध जाने वाली हर आवाज को अनुसूना करने की कोशिश की है। अपने निहित स्वार्थ, जातिवादी पूर्वाग्रह और सरकारी विज्ञापन की नकेल से बंधा मीडिया कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी अलग से व्याख्या करने की जरूरत शायद नहीं है।

Dalits in Bihar's English news media.

An interesting difference between Hindi and English print is in the number of Bhumihar and Rajputs. In comparison to Hindi print, the number of these two castes has declined by more than half (11 per cent of Rajput and Bhumihar, 6 per cent) here. English print is visibly dominated by Brahmins (36 per cent) and Kayasthas (21 per cent). (In English print three Hindu OBCs, one Christian and one Ashraf Muslim [male] are in authoritative post too. In Hindi print and electronic media, these positions are invariably occupied by upper-caste men.)

ELECTRONIC MEDIA: 10 VS 90

The martyred OBC leader Jagdev Prasad gave a slogan: The rule of ten on ninety, won't work/ Ninety are oppressed out of hundred; ninety parts are ours. It was 1971-72. But till today, the socio-political leadership of the OBCs has failed to identify ways to seize power of the knowledge industries. Cultural power seemingly has no value for them. Jagdev Prasad who claimed 90 out of 100 had a second slogan: Raise buffaloes, Build arenas, Do politics. Lalu Prasad has spent 15 years refusing to understand the concept of IT. The backward leaders spoke about education at times but nothing was done at the ground level.

However, the social scene of Hindi-English electronic media is mostly alike. Ninety per cent of the positions are occupied by upper-caste Hindus. Hindu OBCs are 7 per cent. Ashraf Muslims have 3 per cent representation. There are 10 per cent women, all hailing from upper-caste Hindu families. Dalits here are absent altogether.

URDU PRINT: BACKWARD MUSLIM EFFECT

Unlike Hindi and English print media, in many cases, it is heartening to look at the Urdu media. There are five Urdu dailies published from Patna: Tanzim Qaumi, Roznama (Rashtriya Sahara), Sangam, Pindar and Tanzim Faruki. Surprisingly, three of them – Sangam, Pindar and Tanzim Faruki – are owned by Pasmanda (Backward) Muslims. The editors of these three are also from the same communities. Right now it is quite impossible to imagine such a scenario for the Hindi or English media. Indeed, the political movement of social justice for Hindus in Bihar has gone dormant due to its internal contradictions, whereas the Pasmanda movement is still a vibrant one. The last four to five years have witnessed its progress and influence.

In Urdu newspapers, people from Ashraf class represented a total of 66 per cent, while reporters from Pasmanda class had only 26 per cent representation. Keeping these facts in view, it's quite disturbing to note that in Indian journalism as a whole, including Urdu journalism, Dalit Muslims and Muslim women have no representation at all.

One more regressive trend to note is that even Pasmanda-led Urdu newspapers have not tried to loosen the iron grip of religion over the day-to-day life of Muslims.

The next time you read or hear any news from Bihar whether in the Hindi or the English media, just keep in mind through whose eyes and ears and, most importantly, minds the "news" is coming to you.

(English Translation: Shahanshah Ansari)



English media has 7 per cent women's participation. The presence of 4 per cent backward class women also grabs one's attention

अँग्रेजी अखबारों में महिलाओं की भागीदारी 7 फ़ीसदी है। इसमें से पिछड़ी जाति की 4 फ़ीसदी महिलाओं की मौजूदगी भी ध्यान खींचती है।

इनकार करते हुए ही गुज़ार दिए। पिछड़े नेताओं ने कभी शिक्षा की बात की भी तो वह कई कारणों से साक्षरता से आगे नहीं बढ़ सकी।

बहरहाल, हिंदी-अँग्रेजी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सामाजिक परिदृश्य सर्वाधिक एकरस है। इनमें 90 फ़ीसदी पदों पर ऊँची जाति के हिंदुओं का कब्ज़ा है। हिंदू ओबीसी 7 प्रतिशत हैं। अशराफ़ मुसलमानों की नुमाइंदगी 3 फ़ीसदी है। महिलाएँ ज़रूर 10 फ़ीसदी हैं, जो ऊँची जाति के हिंदू परिवारों से आती हैं। दलित यहाँ भी सिर से नदारद है।

उर्दू प्रिंट : पिछड़ा मुसलमान आंदोलन का प्रभाव

हिंदी और अँग्रेजी प्रिंट मीडिया के विपरीत उर्दू मीडिया की ओर देखना कई मामलों में सुखद है। पटना से उर्दू के पाँच दैनिक छपते हैं – कौमी तंजीम, रोज़नामा (राष्ट्रीय सहारा), संगम, पंदार और फ़ारूकी तंजीम। आश्चर्यजनक रूप में इनमें से तीन – संगम, पंदार और फ़ारूकी तंजीम – का मालिकाना हक़ पसमांदा (पिछड़े मुसलमान) तबके के पास है। इन तीनों के संपादक भी इसी समुदाय के हैं। हिंदी या अँग्रेजी मीडिया के संबंध में फ़िलवक्त ऐसी कल्पना भी असंभव है। वस्तुतः बिहार में हिंदुओं का सामाजिक न्याय का राजनीतिक आंदोलन अपने विरोधाभासों में घिर कर मरणान्तर स्थिति में है। जबकि पिछड़े मुसलमानों का आंदोलन एक जीवंत आंदोलन है। पिछले कुछ वर्षों से इसका तेज़ और तेवर देखते बन रहा है।

उर्दू अखबारों के कुल पदों में 66 फ़ीसदी प्रतिनिधित्व अशराफ़ तबके का है जबकि पसमांदा तबके के (ओबीसी) पत्रकार 26 फ़ीसदी हैं। इन तथ्यों के साथ ही यह देखना विचलित करता है कि उर्दू समेत पूरी पत्रकारिता में दलित मुसलमानों और मुसलमान महिलाओं की कोई नुमाइंदगी नहीं है।

एक और प्रतिगामी बात यह है कि पसमांदा नेतृत्व वाले उर्दू अखबार भी मुसमानों के दैनंदिन जावन पर धर्म की जकड़बंदी को ढीला करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे।

आगली बार आप जब बिहार से आने वाली कोई खबर पढ़ें या सुनें, चाहे हिंदी में या अँग्रेजी में, तो ध्यान में एक बात रखें कि किसकी आँखों और कानों – और सबसे महत्वपूर्ण बात – किसके दिमाग़ के द्वारा ये "खबरें" आप तक पहुँच रही हैं।

(अँग्रेजी अनुवाद: शहंशाह अंसारी)